IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में नक्सलवाद: क्या यह समाप्ति की ओर है?

सुश्री पारुल

शोध निर्देशिका

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

गुलनिधेश्वर पाल

परास्नातक छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग

मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर

आरजु

परास्नातक छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग

मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर

सारांश (Abstract)

नक्सलवाद भारत में वामपंथी उग्रवाद का एक प्रमुख रूप है, जिसकी शुरुआत 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई। यह आंदोलन प्रारंभ में भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की मांगों से जुड़ा था, लेकिन समय के साथ यह सशस्त्र संघर्ष में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में यह समस्या मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य भारत के कुछ दुर्गम क्षेत्रों तक सीमित है। पिछले वर्षों में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सुरक्षा, विकास और पुनर्वास नीतियों के कारण नक्सली गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। कई क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में गिरावट, आत्मसमर्पण की बढ़ती प्रवृत्ति और सुरक्षा बलों की बढ़ती उपस्थिति इसके कमजोर होने के संकेत हैं।

हालाँकि, गरीबी, सामाजिक-आर्थिक असमानता और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ अब भी इसकी पूर्ण समाप्ति में बाधा बनी हुई हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

Keywords (मुख्य शब्द)

- नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, माओवाद, आंतरिक सुरक्षा, भारतीय राज्य, विकास और सुरक्षा रणनीति, आदिवासी क्षेत्र, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, नक्सलमुक्त भारत

प्रस्तावना (Introduction)

नक्सलवाद भारत में वामपंथी उग्रवाद) का एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दा है। इसका उद्भव 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में हुए कृषक विद्रोह से माना जाता है, जिसे चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। यह आंदोलन प्रारंभ में भूमि सुधार, सामंतवादी शोषण के विरोध और सामाजिक न्याय की मांगों के इर्द-गिर्द केंद्रित था, लेकिन धीरे-धीरे यह सशस्त्र संघर्ष और राज्य विरोधी हिंसा में परिवर्तित हो गया। समय के साथ यह विचारधारा विभिन्न राज्यों में फैलती गई और 2004 में CPI (Maoist) के गठन के बाद यह अधिक संगठित और हिंसक स्वरूप में सामने आई। वर्तमान में नक्सलवाद मुख्यतः भारत के "रेड कॉरिडोर" क्षेत्र—छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों—तक सीमित है।

भारत सरकार इसे केवल सुरक्षा समस्या नहीं बल्कि विकास और शासन की चुनौती के रूप में देखती है। इसी कारण इसके समाधान हेतु "टू-पिलर अप्रोच" अपनाई गई है, जिसमें एक ओर सुरक्षा बलों के माध्यम से उग्रवाद पर नियंत्रण और दूसरी ओर विकास योजनाओं के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान शामिल है। वर्तमान परिदृश्य में नक्सल हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, परंतु इसकी जड़ें अभी भी उन क्षेत्रों में मौजूद हैं जहाँ गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, भूमि विवाद, और राज्य की सीमित उपस्थिति जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। इसलिए नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से कमजोर अवश्य हुआ है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

नक्सलवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुए सामाजिक-आर्थिक असंतोष और भूमि संबंधी असमानताओं से जुड़ी हुई है। इसका प्रारंभिक स्वरूप 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन में देखा गया, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से कृषक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे वामपंथी विचारकों ने किया था। यह आंदोलन सामंती भूमि व्यवस्था, जमींदारी शोषण और कृषि मजदूरों के अधिकारों के दमन के खिलाफ एक सशस्त्र प्रतिरोध के रूप में उभरा।

1970 के दशक में यह आंदोलन कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, लेकिन इसकी विचारधारा भारत के विभिन्न राज्यों—पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र—तक फैल गई। इस दौरान नक्सली समूहों ने राज्य सत्ता को "दमनकारी संरचना" मानते हुए गुरिल्ला युद्ध (Guerrilla Warfare) की रणनीति अपनाई, जिससे ग्रामीण और वन क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ी।

1990 और 2000 के दशक में नक्सली गतिविधियों में पुनः वृद्धि देखी गई, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी आबादी अधिक थी और विकास की प्रक्रिया धीमी थी। इन परिस्थितियों में विभिन्न माओवादी संगठनों का एकीकरण हुआ और 2004 में "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)" यानी CPI (Maoist) का गठन हुआ। यह संगठन नक्सल आंदोलन को एक संगठित और सशस्त्र विद्रोही शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसने भारत के कई राज्यों में "रेड कॉरिडोर" का विस्तार किया।

समय के साथ भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती मानते हुए व्यापक सुरक्षा अभियानों, विकास योजनाओं और आत्मसमर्पण नीतियों को लागू किया। परिणामस्वरूप, 2010 के बाद से नक्सली हिंसा में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई, लेकिन इसकी वैचारिक जड़ें और सामाजिक आधार कुछ क्षेत्रों में अब भी विद्यमान हैं।

इस प्रकार, नक्सलवाद का ऐतिहासिक विकास यह दर्शाता है कि यह केवल एक अचानक उत्पन्न विद्रोह नहीं था, बल्कि लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और शासन संबंधी कमियों का परिणाम था, जिसने इसे धीरे-धीरे एक संगठित उग्रवादी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया।

3. भारत में नक्सलवाद के कारण (Causes of Naxalism in India)

भारत में नक्सलवाद का उद्भव केवल वैचारिक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण विद्यमान हैं। यह एक बहुआयामी समस्या है, जो मुख्यतः उन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रही है जहाँ राज्य की उपस्थिति कमजोर रही है और विकास का लाभ समान रूप से नहीं पहुँचा है।

3.1 सामाजिक-आर्थिक कारण (Socio-Economic Causes)

नक्सलवाद के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की रही है।

- आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गरीबी और बेरोजगारी
- भूमि वितरण में असमानता और जमींदारी प्रवृत्तियाँ
- वन संसाधनों पर निर्भर समुदायों का विस्थापन
- विकास योजनाओं का सीमित लाभ और धीमा क्रियान्वयन
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी

इन परिस्थितियों ने एक ऐसा असंतोष उत्पन्न किया जिसने नक्सली विचारधारा को जमीन दी।

3.2 राजनीतिक कारण (Political Causes)

राजनीतिक ढांचे की कमजोरियाँ भी नक्सलवाद के विस्तार में सहायक रहीं।

- स्थानीय स्तर पर शासन की कमजोर उपस्थिति
- भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता
- जनजातीय क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी
- विकास योजनाओं में पारदर्शिता का अभाव
- नीति निर्माण में प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी

3.3 प्रशासनिक कारण (Administrative Causes)

प्रशासनिक विफलताएँ भी इस समस्या को बढ़ाने में सहायक रहीं।

- दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की सीमित पहुँच
- पुलिस व्यवस्था और खुफिया तंत्र की प्रारंभिक कमजोरी
- विकास परियोजनाओं का समय पर पूरा न होना
- स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की कमी

3.4 भौगोलिक कारण (Geographical Causes)

भौगोलिक परिस्थितियाँ नक्सलवाद के विस्तार के लिए अनुकूल रही हैं।

- घने वन क्षेत्र और दुर्गम पहाड़ी इलाके
- संचार और परिवहन की सीमित सुविधाएँ
- राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की सीमित पहुँच
- सीमावर्ती और अलग-थलग क्षेत्र

3.5 वैचारिक कारण (Ideological Causes)

नक्सलवाद की वैचारिक नींव माओवादी दर्शन पर आधारित है।

- मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की विचारधारा
- राज्य को "शोषणकारी संरचना" मानना
- सशस्त्र क्रांति को परिवर्तन का माध्यम मानना
- वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर जोर

4. वर्तमान स्थिति (Current Scenario of Naxalism in India)

वर्तमान समय में भारत में नक्सलवाद की स्थिति पहले की तुलना में काफी परिवर्तित हुई है। सुरक्षा बलों की सक्रियता, विकास नीतियों के विस्तार और आत्मसमर्पण/पुनर्वास कार्यक्रमों के कारण नक्सली गतिविधियों में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और कुछ सीमित क्षेत्रों में अब भी इसका प्रभाव देखा जाता है।

4.1 भौगोलिक संकुचन (Geographical Contraction)

- नक्सलवाद अब पहले की तरह व्यापक नहीं रहा है।
- यह मुख्यतः "रेड कॉरिडोर" के कुछ हिस्सों तक सीमित हो गया है।
- छत्तीसगढ़ (बस्तर क्षेत्र), झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमित वन क्षेत्र इसके प्रमुख केंद्र हैं।
- पहले जिन जिलों में सक्रियता अधिक थी, उनमें अब नियंत्रण बढ़ा है।

4.2 हिंसक घटनाओं में गिरावट (Decline in Violence)

- पिछले एक दशक में नक्सली हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।
- सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों और नागरिक हत्याओं में गिरावट दर्ज की गई है।
- कई बड़े नक्सली ऑपरेशनल नेटवर्क कमजोर हुए हैं।

4.3 संगठनात्मक कमजोरी (Organizational Weakness)

- शीर्ष नेतृत्व में लगातार नुकसान हुआ है।
- कई कैडर सदस्य आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
- संगठनात्मक समन्वय पहले की तुलना में कमजोर हुआ है।
- नए भर्ती (recruitment) की गति धीमी हुई है।

4.4 सुरक्षा बलों की बढ़ती उपस्थिति (Increased Security Presence)

- CRPF, CoBRA और राज्य पुलिस की संयुक्त तैनाती बढ़ी है।
- फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) की स्थापना से गहराई तक पहुंच संभव हुई है।
- ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क का उपयोग बढ़ा है।

4.5 विकासात्मक हस्तक्षेप (Developmental Interventions)

- सड़क, पुल और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार
- आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme) का प्रभाव
- सरकारी योजनाओं की पहुंच में वृद्धि

5. सरकारी रणनीतियाँ (Government Strategies to Counter Naxalism)

भारत सरकार ने नक्सलवाद को केवल एक सुरक्षा समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक **सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक चुनौती** के रूप में स्वीकार किया है। इसी कारण इसके समाधान हेतु एक बहुआयामी (Multi-dimensional) रणनीति अपनाई गई है, जिसमें सुरक्षा, विकास, प्रशासन और पुनर्वास—चारों पहलुओं को शामिल किया गया है।

5.1 सुरक्षा आधारित रणनीति (Security Strategy)

नक्सली हिंसा पर नियंत्रण के लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा विकसित किया गया है।

- CRPF, CoBRA, राज्य पुलिस और विशेष बलों की संयुक्त तैनाती
- "ऑपरेशन ग्रीन हंट" और अन्य एंटी-नक्सल अभियानों का संचालन
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) की स्थापना
- खुफिया तंत्र (Intelligence Network) का सुदृढ़ीकरण
- ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग
- सर्च और एन्काउंटर ऑपरेशनों का विस्तार

उद्देश्य: नक्सली संगठनों की सैन्य क्षमता को कमजोर करना

5.2 विकास आधारित रणनीति (Development Strategy)

सरकार ने यह समझा कि केवल सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme)
- ग्रामीण सड़क संपर्क योजना (PMGSY)
- दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
- आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका और रोजगार योजनाएँ
- MGNREGA के माध्यम से ग्रामीण रोजगार

उद्देश्य: स्थानीय जनता को मुख्यधारा से जोड़ना और असंतोष कम करना

5.3 पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति (Rehabilitation Policy)

नक्सल आंदोलन को कमजोर करने के लिए आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित किया गया है।

- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता
- कौशल विकास (Skill Development) प्रशिक्षण
- पुनर्वास केंद्रों की स्थापना
- समाज में पुनः एकीकरण (Reintegration) की प्रक्रिया
- कानूनी मामलों में राहत नीतियाँ

उद्देश्य: कैडर को हिंसा से हटाकर मुख्यधारा में लाना

5.4 प्रशासनिक एवं विधिक सुधार (Administrative & Legal Measures)

- पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण (PESA Act)
- वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act, 2006) का क्रियान्वयन
- स्थानीय शासन में आदिवासी भागीदारी बढ़ाना
- भ्रष्टाचार नियंत्रण और पारदर्शिता पर जोर
- पुलिस सुधार और प्रशिक्षण

6. क्या नक्सलवाद समाप्ति की ओर है? (Critical Analysis: Is Naxalism Heading Towards Extinction?)

वर्तमान समय में नक्सलवाद की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह आंदोलन पहले की तुलना में **काफी कमजोर (significantly weakened)** हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी। यह एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है जिसे "**declining but persisting phase**" कहा जा सकता है।

6.1 सकारात्मक संकेत (Indicators of Decline)

पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं, जो नक्सलवाद की कमजोरी को दर्शाते हैं:

- नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में लगातार कमी आई है।
- हिंसक घटनाओं (violence incidents) में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है।
- सुरक्षा बलों द्वारा कई शीर्ष नक्सली नेताओं का सफाया या आत्मसमर्पण कराया गया है।
- नए कैडर की भर्ती (recruitment) में कमी आई है।
- स्थानीय जनता का समर्थन पहले की तुलना में कमजोर हुआ है।
- कई पुराने "रेड कॉरिडोर" क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति मजबूत हुई है।

6.2 सुरक्षा और विकास का प्रभाव (Impact of Security & Development Policies)

भारत सरकार की संयुक्त रणनीति ने नक्सलवाद को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और आक्रामक अभियानों ने संगठनात्मक ढांचे को तोड़ा है।
- फॉरवर्ड बेस कैंप और इंटेलिजेंस नेटवर्क ने नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाया है।
- सड़क, संचार और शिक्षा जैसी विकास योजनाओं ने ग्रामीण असंतोष को कम किया है।
- आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति ने नक्सली कैडर को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है।

6.3 सीमाएँ और चुनौतियाँ (Limitations and Continuing Challenges)

हालांकि गिरावट स्पष्ट है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं:

- छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कुछ दुर्गम वन क्षेत्रों में अब भी सक्रियता बनी हुई है।
- नक्सलवाद की वैचारिक जड़ें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।
- गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता अभी भी कुछ क्षेत्रों में मौजूद हैं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में राज्य की पूर्ण उपस्थिति अभी भी एक चुनौती है।
- छोटे-छोटे गुटों (splinter groups) का अस्तित्व बना हुआ है।

7. समग्र मूल्यांकन (Overall Assessment)

नक्सलवाद अब एक **mass movement** नहीं रहा, बल्कि यह एक **fragmented and regionally limited threat** बन गया है। इसकी संगठनात्मक क्षमता, जनाधार और संचालन क्षमता पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है।

इसलिए इसे "पूर्ण समाप्ति" की स्थिति में नहीं बल्कि "**अंतिम चरण की गिरावट (terminal decline phase)**" में माना जा सकता है।